

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3256]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 22, 2017/अग्रहायण 1, 1939

No. 3256]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 22, 2017/AGRAHAYANA 1, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2017

का.आ. 3710 (अ). — प्रारूप अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1969 (अ), तारीख 3 जून, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त राजपत्र, की प्रतियां जनता को 3 जून, 2016 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई टीका टिप्पणियां/आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

और, तालरा वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में लगभग 46.48 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।

और, इस अभयारण्य में वनस्पति और जीव जन्तु की समृद्ध जैविकीय महत्व का प्रतिनिधित्व है। अभयारण्य तेंदुआ (*पेन्थेरा पार्डस*), काला भालू (*अरसस अमरीकंस*), मुंजक (*मुनटीक्स स्प.*), गोरल (*नोइमोरहेट्टस स्प.*), और तीतर जैसे कलीज (*लोफुरा लेयकोमेलनोस*), लाल जंगली मुर्गी (*गल्लुस गल्लुस*), मोनल (*लोफोफोरुस स्प.*), कोकलस (*पुकरासीअ मकरोलोफो*), और पक्षियों जैसे काला तीतर (मेलनोपेरदीक्स नीगर), गिद्ध (अगयपीअस मोनाचुस), गरूड़ (हलीअइइटुस स्प.), चकोर (अलेक्टोरीस चुकर), उल्लू (स्टीगीफोरमेस स्प), आदि के लिए वास है;

और, तालरा वन्यजीव अभयारण्य, के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों का प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश राज्य में तालरा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 मीटर से 3.87 किलोमीटर के क्षेत्र को तालरा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार है, अर्थात् :

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं—(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन तालरा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 मीटर से 3.87 किलोमीटर तक फैला है, क्षेत्र 22.56 वर्ग किलोमीटर है इसका शून्य विस्तार उत्तराखंड की अन्तराज्य सीमा के कारण दक्षिण की तरफ है।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के तालरा वन्यजीव अभयारण्य का मानचित्र उपाबंध I के रूप में उपाबद्ध है। वन्यजीव अभयारण्य की सीमाएं और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-निर्देशांकज की सूची उपाबंध I(क) के रूप में उपाबद्ध है।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का सीमा का वर्णन उपाबंध II के रूप में उपाबद्ध है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत कोई ग्राम नहीं आता है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना —(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) आंचलिक महायोजना के द्वारा तैयार किए गए अधिसूचना में उल्लेखित शर्त के अनुरूप होंगे और पर्यावरणीय प्रभाव भी शामिल होंगे।

(3) आंचलिक महायोजना राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति से राज्य सरकार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य में भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश का सिद्धांत, यदि कोई हो द्वारा तैयार की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना, राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार की जाएगी अर्थात्:--

- (i) पर्यावरण ;
- (ii) वन ;
- (iii) शहरी विकास ;
- (iv) पर्यटन ;
- (v) नगरपालिका ;
- (vi) राजस्व ;
- (vii) कृषि ;
- (viii) सिंचाई;
- (ix) लोक निर्माण विभाग; और
- (x) हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(6) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूलता का संवर्धन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरणों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(8) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, जनजातीय क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी। योजना का मानचित्र में विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग की विशेषताओं के विवरण किया जाएगा।

(9) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिकी अनुकूल विकास के लिए विनियमित करेगी और अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध, विनियम और संवर्धित क्रियाकलापों का अनुसरण करेगी।

(10) आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के संबंध में अपने कार्यों के बाहर ले जाने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) भू-उपयोग - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ

(2) के अधीन सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

- (i) पारिस्थितिकी अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;
- (ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का सन्निर्माण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) वर्षा जल संचय; और;
- (v) कुटीर उद्योग जिसके अंतर्गत ग्राम उद्योग, सुविधा भंडार और स्थानीय सुख-सुविधाएं भी हैं:

परंतु यह और भी कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंज्ञात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

परंतु यह और भी कि हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत - आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के जल आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा जल आवाह क्षेत्रों में विकास

क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना में प्रतिषिद्ध और निर्बंधित करने के लिए ऐसी रीति से जल आवाह प्रबंधन योजना के मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे।

(3) पारिस्थितिकी-पर्यटन – (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना के भाग बनेंगे।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वन और पर्यावरण विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के परामर्श से तैयार की जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का एक संघटक होगी।

(घ) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) तालरा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा 1 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इसमें जो भी नजदीक हो होटल और रिसोर्ट के नए संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे। तथापि वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटल और रिसोर्टों की स्थापना को पूर्व परिभाषित और विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पारिस्थितिकी पर्यटन कार्यक्रमों के लिए पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गनिर्देशों के अनुसार होगा जिसमें पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी शिक्षा और पारिस्थितिकी विकास को महत्व दिया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा।

(4) नैसर्गिक विरासत – पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा।

(5) मानव निर्मित विरासत स्थल - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनका परिक्षण किया जाएगा तथा इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार की जाएगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी।

(6) ध्वनि प्रदूषण – राज्य सरकार का प्रदूषण विभाग या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विनियमों का ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 कार्यान्वयन करेगा।

(7) वायु प्रदूषण – पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का नियंत्रण और वायु निवारण (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में किया जाएगा।

(8) बहिस्त्राव का निस्सारण - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) ठोस अपशिष्ट — ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा--

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान और प्रबंधन समय-समय पर संशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ) तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकता है।

(10) जैव चिकित्सीय अपशिष्ट- जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा—

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.का.नि 343 (अ) तारीख 28 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकता है।

(11) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार और भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित प्रकाशित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के अनुसार किया जाएगा।

(12) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन, संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार और भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित प्रकाशित अधिसूचना सं.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के अनुसार किया जाएगा।

(13) इलैक्ट्रानिकी-अपशिष्ट:- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में इलैक्ट्रानिकी-अपशिष्ट नियम, 2016, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित प्रकाशित किए गए थे, के अनुसार किया जाएगा।

(14) यानीय परिवहन: - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुमोदित होन तक, राज्य स्तरीय पारिस्थितिकी संवेदी जोन मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(15) औद्योगिक ईकाइयां: - (क) प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को सिवाय विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(ख) जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग की प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन में स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(16) यदि वह आवश्यक समझती है, तो इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, अन्य उपायों निर्दिष्ट करेगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में

विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां प्रतिषिद्ध हैं, सिवाय निवासियों की सद्भावपूर्ण घरेलू आवश्यकताओं के नहीं होगी, जिसके अंतर्गत गृहों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए मिट्टी की खुदाई और व्यक्तिक उपभोग के लिए गृहों के निर्माण के लिए देशी टाइलों या ईंटों का संनिर्माण भी है। (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडावर्मन थिरूमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।
(2)	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
(3)	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(4)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नई प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों या उसके विस्तार की अनुमति दी जाएगी। पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर प्रदूषित उद्योग अनुज्ञात होंगे। इसके अतिरिक्त गैर प्रदूषित कुटीर उद्योग का संवर्धन किया जाएगा।
(5)	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(6)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(7)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्त्राव।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(8)	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(9)	ईट भट्टों की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
विनियमित क्रियाकलाप		
(10)	होटलों और रिसोर्टों का वाणिज्यिक स्थापना।	राष्ट्रीय पार्क की सीमा के 1 किलोमीटर के भीतर नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना को सिवाय पारिस्थितिकी के अनुकूल पर्यटन कार्यक्रमों से संबंधित पर्यटकों के लिए अस्थायी आवास के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। परन्तु संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार यथा लागू पर्यटन महायोजना के अनुरूप होगा।
(11)	संनिर्माण क्रियाकलाप।	संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: (क) परन्तु स्थानीय लोगों को पैरा 6 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी।

		(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण; (ii) अवसंरचना और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण; (iii) कुटीर उद्योगों, जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधा भण्डार और स्थानीय सुविधाएं, जो पारिस्थितिकी पर्यटन की सहायता करती हैं, जिसके अंतर्गत गृह वास है, सम्मिलित हैं; और (iv) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध संबंधित कार्यकलाप :
(12)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण।	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/ अबशिष्टों के बहिर्स्राव के जल निकायों में प्रवेश होने से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/अबशिष्टों के बहिर्स्राव को लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
(13)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रालाइट, आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(14)	वायु और यानीय प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(15)	सतह और भूजल के वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(16)	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कोई कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी।
(17)	प्रवासी चरवाहे।	लागू विधियों और आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
(18)	विद्युत का परिनिर्माण और विद्युत लाइनों का इन्सुलेशन और संचार टावर तथा केबलों और केबलों को बिछाना और अन्य अवसंरचनाएं।	लागू विधियों के अधीन विनियमित। भूमिगत केबलीकरण का संवर्धन किया जाएगा।
(19)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे।
(20)	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(21)	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एनटीएफपी)।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(22)	प्राकृतिक जल संसाधनों का वाणिज्यिक उपयोग, जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(23)	रात्रि में यानीय यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
(24)	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(25)	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(26)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(27)	मछली पकड़ना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(28)	जल परिवहन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(29)	अवसंरचना, जिसके अंतर्गत नागरिक सुविधाएं हैं।	न्यूनीकरण की उपायों के साथ, लागू विधियों नियमों और विनियमों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा।

(30)	खुले कुआ, बोर कुआ, आदि के लिए कृषि और अन्य उपयोग के लिए।	विनियमित और कार्यकलाप की कठोरता से समुचित प्राधिकारी द्वारा मानीटरी की जाएगी
(31)	ठोस जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(32)	पारिस्थितिकी-पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
संबंधित क्रियाकलाप		
(33)	स्थानीय समुदायों द्वारा चलाई जा रही कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, पशुपालन, और मत्स्य पालन।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात।
(34)	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(35)	सभी कार्यकलापों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(36)	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर प्रदूषणकारी उद्योग और गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से स्वदेशी सामग्री से उत्पादों का उत्पादन कर रहे हैं, का सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा।
(37)	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(38)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(39)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	जैव गैस, सौर प्रकाश आदि का संवर्धन किया जाएगा।
(40)	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(41)	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(42)	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(43)	निम्नकोटिकृत /वनों/ पर्यावासों का प्रत्यावर्तन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(44)	पर्यावरण जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. मानीटरी समिति- केंद्रीय सरकार, तीन महीने की अवधि के लिए अंतिम अधिसूचना के निगरानी प्रभावी के लिए मानीटरी समिति गठित करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-

- (i) संबंधित जिला मजिस्ट्रेट, शिमला -अध्यक्ष;
- (ii) पारिस्थितिकी और पर्यावरण क्षेत्र से हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाए वाला एक विशेषज्ञ -अध्यक्ष;
- (iii) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा गैर सरकारी संगठन (पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले, जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) गैर सरकारी संगठन का तीन वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक प्रतिनिधि - सदस्य;
- (iv) हिमाचल प्रदेश राज्य जैव-विविधता बोर्ड का सदस्य/सचिव या सदस्य -सदस्य;-
- (v) कार्यपालक इंजीनियर, हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड -सदस्य ;
- (vi) क्षेत्र का ज्येष्ठ योजनाकार - सदस्य;
- (vii) उप वन परिरक्षक (वन्यजीव), शिमला -अध्यक्ष;
- (viii) प्रभागीय वन अधिकारी, (प्रादेशिक), रोह्रु - सदस्य-सचिव।

6. निर्देश निबंधन (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

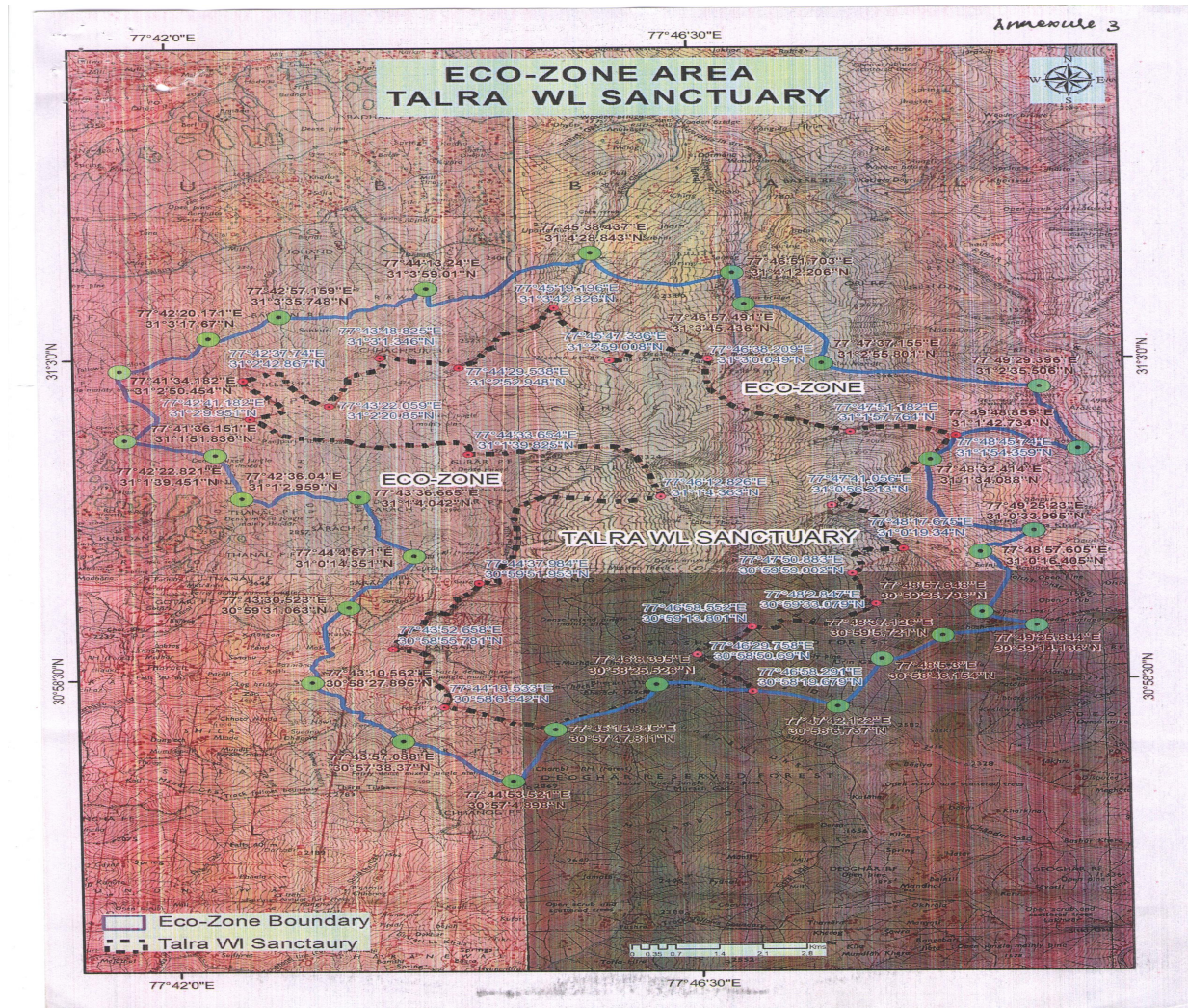
- (2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन (3) वर्ष या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का गठन किए जाने तक होगा।
- (3) इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन महीने के अंतर्गत पहली निगरानी समिति का गठन किया जाएगा।
- (4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित राज्य स्तरीय पारिस्थितिकी संवेदी जोन मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।
- (5) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (6) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।
- (7) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
- (8) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन, और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उपाबंध III में उपबंधित रूप में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।
- (9) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।
- 7. अतिरिक्त उपाय:** इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।
- 8. सुप्रीम कोर्ट आदि के आदेश.-** इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

[फा.सं. 25/17/2016-ईएसजेड-आरई]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

तालरा वन्यजीव अभयारण्य, हिमाचल प्रदेश का मानचित्र



उपाबंध I(ख)

तालरा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भू- निर्देशांक

क्र.सं	अक्षांश	देशांतर
1.	31° 3'42.826" उ	77° 45'19.196" पू
2.	31° 2'59.008" उ	77° 45'47'47.336" पू
3.	31° 3'0.049" उ	77° 46'38.209" पू

4.	31° 1' 57.764" उ	77° 47' 51.182" पू
5.	31° 1' 54.359" उ	77° 48' 45.74" पू
6.	31° 0' 56.213" उ	77° 47' 41.056" पू
7.	31° 0' 19.34" उ	77° 48' 17.675" पू
8.	30° 59' 59.002" उ	77° 47' 50.883" पू
9.	30° 59' 33.079" उ	77° 48' 2.847" पू
10.	30° 59' 13.801" उ	77° 46' 58.552" पू
11.	30° 58' 50.69" उ	77° 46' 29.758" पू
12.	30° 58' 19.679" उ	77° 46' 58.291" पू
13.	30° 58' 6.942" उ	77° 44' 18.533" पू
14.	30° 58' 55.781" उ	77° 43' 52.658" पू
15.	30° 59' 51.953" उ	77° 44' 37.984" पू
16.	31° 1' 4.363" उ	77° 46' 12.826" पू
17.	31° 1' 39.825" उ	77° 44' 33.654" पू
18.	31° 2' 9.951" उ	77° 42' 41.182" पू
19.	31° 2' 42.867" उ	77° 42' 37.74" पू
20.	31° 2' 20.85" उ	77° 43' 22.059" पू
21.	31° 3' 1.346 " उ	77° 43' 48.825" पू
22.	31° 2' 52.948" उ	77° 44' 29.538" पू

पारिस्थितिकी संवेदी जोन में तालरा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भू-निर्देशांक

क्र.सं	अक्षांश	देशांतर
1.	31° 4' 28.843"उ	77° 45' 38.437" पू
2.	31° 4' 12.206" उ	77° 46' 51.703" पू
3.	31° 3' 45.436"उ	77° 46' 57.491"पू
4.	31° 2' 55.801"उ	77° 47' 37.155"पू
5.	31° 2' 35.506"उ	77° 49' 29.396"पू
6.	31° 1' 34.088"उ	77° 48' 32.414"पू
7.	31° 0' 33.995"उ	77° 49' 25.234"पू
8.	31° 0' 16.405"उ	77° 48' 57.605"पू
9.	30° 59' 25.796"उ	77° 48' 57.648"पू
10.	30° 59' 14.136"उ	77° 49' 25.844"पू
11.	30° 59' 5.721"उ	77° 48' 37.126"पू
12.	30° 58' 46.154"उ	77° 48' 5.3"पू
13.	30° 58' 6.767"उ	77° 47' 42.122"पू
14.	30° 58' 25.526"उ	77° 46' 8.395"पू
15.	30° 57' 47.811"उ	77° 45' 15.845"पू
16.	30° 57' 4.898"उ	77° 44' 53.521"पू
17.	30° 57' 38.37"उ	77° 43' 57.088"पू
18.	30° 58' 27.895"उ	77° 43' 10.562"पू
19.	30° 59' 31.063"उ	77° 43' 30.523"पू
20.	31° 0' 14.351" उ	77° 44' 4.671"पू
21.	31° 1' 4.042"उ	77° 43' 36.665"पू
22.	31° 1' 2.959"उ	77° 42' 36.04"पू
23.	31° 1' 39.451"उ	77° 42' 22.821"पू
24.	31° 1' 51.836"उ	77° 41' 36.151"पू
25.	31° 2' 50.454"उ	77° 41' 34.182"पू
26.	31° 3' 17.67"उ	77° 42' 20.171"पू
27.	31° 3' 35.748"उ	77° 42' 57.159"पू
28.	31° 3' 59.01"उ	77° 44' 13.24"पू

उपाबंध II**पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन**

उत्तर:

उत्तराखंड में 506734"उ, 77°49'48.859"पू और 31°01'42.734"उ से आरंभ होकर, जाखू मंदिर और लकड़ी पुल और नाली खाद की श्रेणी के साथ ऊपर की ओर जाती है। छजपुर संरक्षित वन से होते हुए 77°45'38.437" पू और 31°04'28.843"उ र रविगड़ श्रेणी के साथ और जोहन गड़ के ऊपर और इसके बाद श्रेणी 77°41'34.182" पू और 31°02'50.454"उ के साथ जाती है।

पूर्व:

यह रिंजा डी.पी.एफ से होते हुए सोम खाद में 77°42'22.821"पू और 31°01'39.451"उ जाती है और रियल नाला के थानल डी.पी.एफ के साथ चैखरी नाला के ऊपर जाती है और गुरर एफ.आर.एच के श्रेणी के साथ, इसके बाद सरीच डी.पी.एफ के साथ और 77°43'10.562"पू और 30°58'27.895"उ से होते हुए कतह, मकरु के निजी भूमि की ओर जाती है। इसके बाद श्रेणी के साथ 77°44'53.521"पू और 30°57'4.898"उ उत्तराखंड राज्य सीमा की ओर जाती है।

दक्षिण:

यह उत्तराखंड राज्य सीमा और फासा धार में 77°47'42.122"पू और 30°58'6.767"उ तालरा वन्यजीव अभयारण्य के साथ मुड़ती है।

पश्चिम:

तालरा वन्यजीव अभयारण्य आरंभिक बिंदु की उत्तर सीमा के 77°49'48.859"पू और 31°01'42.734"उ के साथ मुड़कर और इसके अतिरिक्त इसके साथ मुड़कर 77°48'32.414"पू और 31°01'34.088"उ इसके बाद 77°49'25.23"पू और 31°00'33.995"उ के दौनेहर ग्राम के निजी भूमि और ओछा खाद के ऊपर जाती है, इसके बाद शाशन ग्राम के सैनेज ग्राम के साथ गोलथर धार और लोदारु खाद के साथ ऊपर की ओर जाती है। इसके अतिरिक्त यह उरिन गड़ के साथ मुड़कर और इसके बाद श्रेणी के साथ 77°47'42.122"पू और 30°58'6.767"उ ऊपर की ओर जाती है।

उपाबंध III**पारिस्थितिकी संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का प्रारूप**

1. बैठकों की संख्या और तिथि।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st November, 2017

S.O.3710(E).— WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1969 (E) dated the 3rd June, 2016, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And Whereas, copies of the Gazette containing the draft notification were made available to the public on the 3th June, 2016;

And Whereas, no comments/objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

And Whereas, the Talra Wildlife Sanctuary is situated in Shimla District of Himachal Pradesh and is spread over an area of about 46.48 square kilometers.

And Whereas, the flora and fauna represent rich biological significance of this sanctuary. The sanctuary is the habitat for leopard (*Panthera pardus*), Black bear (*Ursus americanus*), barking deer (*Muntiacus sp.*), ghoral (*Naemorhedus sp.*), and pheasants such as Kalij (*Lophura leucomelanos*), Red Jungle fowl (*Gallus gallus*), Monal (*Lophophorus sp.*), Koklash (*Pucrasia macrolopha*) and birds such as Black partridge (*Melanoperdix niger*), Vultures (*Aegypius Monachus*), eagle (*Haliaeetus sp.*), Chakor (*Alectoris chukar*), Owl (*Strigiformes sp.*), etc.;

And Whereas, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Talra Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent ranging from 0 metres to 3.87 kilometres around the boundary of Talra Wildlife Sanctuary in the State of Himachal Pradesh as the Talra Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

- 1. Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.**- (1) The Eco-Sensitive Zone covers an area of 22.56 sq. kms with an extent ranging from 0 metres to 3.87 kilometres around the boundary of Talra Wildlife Sanctuary. Zero extent is towards Southern side due to inter-state boundary with Uttarakhand.
- (2) The map of Talra Wildlife Sanctuary demarcating the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure I**. The list of geo co-ordinates of the boundaries of Wildlife Sanctuary and Eco Sensitive Zone is at **Annexure I (A)**.
- (3) The boundary description of the Eco-Sensitive Zone is at **Annexure II**.
- (4) No villages fall within the Eco-Sensitive Zone.

- 2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-** (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.
- (2) The Zonal Master Plan so prepared shall commensurate with the stipulation specified in the Notification and include the environmental implications.
- (3) The Zonal Master Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.
- (4) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
- (5) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-
- (i) Environment;
 - (ii) Forest;
 - (iii) Urban Development;
 - (iv) Tourism;
 - (v) Municipal;
 - (vi) Revenue;
 - (vii) Agriculture;
 - (viii) Irrigation;
 - (ix) Public Works Department; and
 - (x) Himachal Pradesh State Pollution Control Board.
- (6) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (7) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (8) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green areas such as parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes, wetlands and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.
- (9) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and shall follow prohibited, regulated and promoted activities specified in the Notification so as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.
- (10) The Zonal Master Plan shall be a reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions with respect to the provisions given in this notification.

3. **Measures to be taken by State Government.**-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Landuse.**- Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

- (i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, for Eco-friendly tourism activities;
- (ii) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (iii) Small scale industries not causing pollution;
- (iv) Rainwater harvesting; and
- (v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities;

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of the Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural Springs.**- The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the catchment management plan shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit or and restrict development activities within the catchment areas.

(3) **Eco-Tourism.**-(a)The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Eco-Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism, Government of Himachal Pradesh in consultation with Department of Revenue and Forests, Government of Himachal Pradesh.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities relating to tourism shall be regulated as under, namely.-

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the Talra Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-Sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural Heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.**- The Environment Department of the State Government or Bihar State Pollution Control Board shall implement the regulations for control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions stipulated of The Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) **Air pollution.**- Regulations for the control of air pollution in the Eco-Sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder shall be complied with.

(8) **Discharge of effluents.**- The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made therein. –

(9) **Solid wastes.** - Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) The solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** Bio medical waste management shall be as under:

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016, as amended from time to time.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) **Plastic Waste Management.-** The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R 340 (E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) **Construction and Demolition Waste Management.-** The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) **E-waste.-** The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) **Vehicular traffic. -** The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) **Industrial units.-**

(a) No establishment of new wood based industries within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the law.

(b) No establishment of any new industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted.

(16) The Central Government and the State Government shall specify other measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated or promoted within the Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder and shall be regulated in the manner specified in the Table below, namely:

Sl. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
5.	Establishment of new major hydro-electric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
8.	Use of plastic bags by shopkeepers.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
Regulated Activities		
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities. Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever

		is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
11.	Construction activities	No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: (a) Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 6 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as: (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Cottage industries including village industries; convenience stores & local amenities supporting eco-tourism including home stays; and (iv) Promoted activities listed in this Notification.
12.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
13.	Under taking other activities related to tourism like over flying the ESZ area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable law
14.	Air, Vehicular and Noise Pollution.	Regulated under applicable laws.
15.	Commercial extraction of surface and ground water	Regulated under applicable law.
16.	Felling of Trees	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
17.	Migratory graziers.	Regulated under applicable laws and as per Zonal Master Plan.
18.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable law. Underground cabling may be promoted.
19.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
20.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
21.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.

22.	Commercial use of Natural water Resource including Ground water Harvesting.	Regulated under applicable laws.
23.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
24.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
25.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
26.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
27.	Fishing.	Regulated under applicable laws
28.	Water Transportation.	Regulated under applicable laws
29.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
30.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
31.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws
32.	Eco-tourism	Regulated under applicable laws
Promoted Activities		
33.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
34.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
35.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
36.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries termed as White Category as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
37.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
38.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
39.	Use of renewable energy and fuels	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted
40.	Agro-Forestry	Shall be actively promoted.

41.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
42.	Skill Development	Shall be actively promoted.
43.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat	Shall be actively promoted.
44.	Environmental Awareness	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- The Central Government within three months of this Notification, constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of the final notification, comprising of the following, namely:-

- | | | |
|--------|---|-------------------|
| (i) | District Magistrate, Shimla – | Chairman; |
| (ii) | An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Himachal Pradesh for a period of three years- | Member; |
| (iii) | One representative of non-Governmental Organisation - Member (Working in the field of environment including heritage Conservation) to be nominated by the Government of Himachal Pradesh for a period of three years- | Member; |
| (iv) | Member Secretary/Member or nominee from Himachal State Biodiversity Board- | Member; |
| (v) | Executive Engineer, Himachal Pradesh State Pollution Control Board – | Member; |
| (vi) | Senior Town Planner of the area – | Member; |
| (vii) | Deputy Conservator of Forests (Wildlife), Shimla – | Member; |
| (viii) | Divisional Forest Officer (Territorial), Rohru - | Member-Secretary. |

6. Terms of Reference:

- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of the final Notification.
- (2) The tenure of the Monitoring committee is for three (3) years or till the Constitution of the new Committee by the State Government.
- (3) The first Monitoring Committee shall be constituted within three months from the date of publication of this Notification.
- (4) (3) The Monitoring Committee shall not allow the activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, including the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof. Only white categories of industries shall be considered as specified in the guidelines issued by the CPCB for “classification of Industries, 2016”.
- (5) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.
- (6) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Commissioner shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.

- (7) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (8) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wild Life Warden of the State under intimation to this Ministry as per proforma appended at **Annexure III**.
- (9) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional measures.- Additional measures.- The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Supreme Court, etc. orders; The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

[F.No.25/17/2016-ESZ-RE]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

Map of Talra Wildlife Sanctuary, Himachal Pradesh



Annexure-I (B)**Geo Co-ordinates of boundary of Talra Wildlife Sanctuary**

Sl. No.	Latitude	Longitude
1.	31° 3'42.826"N	77° 45'19.196" E
2.	31° 2'59.008" N	77° 45'47'47.336"E
3.	31° 3'0.049" N	77° 46'38.209"E
4.	31° 1' 57.764" N	77° 47'51.182"E
5.	31° 1'54.359" N	77° 48'45.74" E
6.	31° 0'56.213" N	77° 47'41.056" E
7.	31° 0'19.34" N	77° 48'17.675" E
8.	30° 59' 59.002"N	77° 47'50.883"E
9.	30°59' 33.079" N	77° 48'2.847" E
10.	30° 59' 13.801" N	77° 46'58.552"E
11.	30° 58' 50.69" N	77° 46'29.758"E
12.	30° 58' 19.679"N	77° 46'58.291"E
13.	30° 58' 6.942" N	77° 44'18.533"E
14.	30° 58' 55.781" N	77° 43'52.658"E
15.	30° 59' 51.953" N	77° 44'37.984"E
16.	31° 1' 4.363" N	77° 46'12.826"E
17.	31° 1' 39.825" N	77° 44'33.654"E

18.	31° 2' 9.951" N	77° 42' 41.182" E
19.	31° 2' 42.867" N	77° 42' 37.74" E
20.	31° 2' 20.85" N	77° 43' 22.059" E
21.	31° 3' 1.346 " N	77° 43' 48.825" E
22.	31° 2' 52.948" N	77° 44' 29.538" E

Geo Co-ordinates of Eco Sensitive Zone of Talra Wildlife Sanctuary

Sl. No.	Latitude	Longitude
1.	31° 4' 28.843" N	77° 45' 38.437" E
2.	31° 4' 12.206" N	77° 46' 51.703" E
3.	31° 3' 45.436" N	77° 46' 57.491" E
4.	31° 2' 55.801" N	77° 47' 37.155" E
5.	31° 2' 35.506" N	77° 49' 29.396" E
6.	31° 1' 34.088" N	77° 48' 32.414" E
7.	31° 0' 33.995" N	77° 49' 25.234" E
8.	31° 0' 16.405" N	77° 48' 57.605" E
9.	30° 59' 25.796" N	77° 48' 57.648" E
10.	30° 59' 14.136" N	77° 49' 25.844" E
11.	30° 59' 5.721" N	77° 48' 37.126" E
12.	30° 58' 46.154" N	77° 48' 5.3" E
13.	30° 58' 6.767" N	77° 47' 42.122" E
14.	30° 58' 25.526" N	77° 46' 8.395" E

15.	30° 57' 47.811''N	77° 45' 15.845''E
16.	30° 57' 4.898''N	77° 44' 53.521''E
17.	30° 57' 38.37''N	77° 43' 57.088''E
18.	30° 58' 27.895''N	77° 43' 10.562''E
19.	30° 59' 31.063''N	77° 43' 30.523''E
20.	31° 0' 14.351'' N	77° 44' 4.671''E
21.	31° 1' 4.042''N	77° 43' 36.665''E
22.	31° 1' 2.959''N	77° 42' 36.04''E
23.	31° 1' 39.451''N	77° 42' 22.821''E
24.	31° 1' 51.836''N	77° 41' 36.151''E
25.	31° 2' 50.454''N	77° 41' 34.182''E
26.	31° 3' 17.67''N	77° 42' 20.171''E
27.	31° 3' 35.748''N	77° 42' 57.159''E
28.	31° 3' 59.01''N	77° 44' 13.24''E

Annexure II

Boundary Description of Eco-Sensitive Zone of Talra Wildlife Sanctuary, Himachal Pradesh

NORTH: Starts from 77° 49' 48.859''E & 31° 01' 42.734''N, at Uttarakhand 506734''N, then up to Jakhu Mandir and along ridge up to wooden bridge and Nalli Khad. Then through Chhajpur RF up to 77° 45' 38.437''E & 31° 04' 28.843''N and along Rawingarh ridge and up to Johan Gad and then along ridge to 77° 41' 34.182''E & 31° 2' 50.454''N

EAST: It follows up to Som Khad at 77° 42' 22.821''E & 31° 1' 39.451''N through Rinja DPF and up to Chaikhari Nallah along Thanal DPF up to Real Nallah and along the ridge up to Gurar FRH, then along Sarech DPF and private lands of Katah, Makroh through 77° 43' 10.562''E & 30° 58' 27.895''N. Then along ridge up to 77° 44' 53.521''E & 30° 57' 4.898''N and the up to Uttarakhand State boundary.

SOUTH: It moves along the Uttarakhand State boundary and Talra WLS boundary up to Phasa Dhar at 77° 47' 42.122''E & 30° 58' 6.767''N

WEST: The starting point of north boundary at $77^{\circ} 49' 48.859''$ E & $31^{\circ} 01' 42.734''$ N moves up to Talra WLS boundary and further moves along this up to $77^{\circ} 48' 32.414''$ E & $31^{\circ} 01' 34.088''$ N, then up to Ochha Khad and private lands of Daunehr village at $77^{\circ} 49' 25.23''$ E & $31^{\circ} 0' 33.995''$ N, then along Sainj village, Golthar Dhar up to Lodaru Khad, the along Shashan village. It further moves along Urin Gad and then along ridge up to $77^{\circ} 47' 42.122''$ E & $30^{\circ} 58' 6.767''$ N.

Annexure III

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.